

LOK SABHA

Monday, 13th May, 1957

The Lok Sabha met at Twelve of the Clock.

[MR. SPEAKER in the Chair]

(No Questions)

MEMBERS SWORN

Mr. Speaker: Those hon. Members who have not already taken the oath will do so now.

Shri Ram Sahai (Khajuraho).

Shri Amjad Ali (Dhubri).

Shri Digvijaya Narain Singh (Pupri).

Shri V. P. Nayar (Quilon).

Shrimati Rani Kesharkumari Devi (Raipur—Reserved).

Shri M. Khuda Baksh (Murshidabad).

Shri Sadhan Gupta (Calcutta—East).

Shri Suresh Chandra Choudhury (Dumka).

Mr. Speaker: Is there any other Member who has not so far taken the oath? None.

PAPERS LAID ON THE TABLE

PRESIDENT'S ADDRESS

Secretary: Sir, I lay on the Table a copy of the President's Address to both Houses of Parliament assembled together on the 13th May, 1957.

PRESIDENT'S ADDRESS

राष्ट्रपति : संसद् के सदस्यगण, देश के लगभग २० करोड़ निर्वाचकों द्वारा चुने गए

20 L.S.D.—1

आप लोगों ने और राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों ने, हमारे संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार, एक बार फिर इस गणराज्य के राष्ट्रपति के उच्च पद के लिए मुझे चुना है। मैं इस आदर से पूरी तरह अभिन्न हूँ और आपने जो विश्वास मुझ में प्रकट किया है उसके लिए आपका आभारी हूँ। मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि जिस विश्वास और प्रेम का इतने समय से मैं पात्र रहा हूँ, सदा उसके योग्य बना रहूँ।

हमारे गणराज्य के इतिहास में यह दूसरी संसद् है और इसके सदस्यों के रूप में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप में से कुछ लोग संसद् के किसी एक सदन के सदस्य रहे हैं अथवा राज्यों के विधान मंडलों से बहुमूल्य सांसद अनुभव अपने साथ ले कर आए हैं। आप लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो संसद् के लिए पहली बार चुने गए हैं। आप सब को अपने जीवन में तथा संसद् के सदस्य के रूप में इस संसद् के अन्दर और चुनाव क्षेत्रों में अपने देशवासियों की सेवा के रचनात्मक काम के लिए विभिन्न और व्यापक अवसर मिलेंगे।

हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यह दूसरा साल है। योजना के पहले वर्ष में हमारी गति अनिवार्य रूप से कुछ मन्द हुई है, जिसका कारण किसी हद तक राज्यों का पुनर्गठन है। इसके कारण हम पर अधिक दबाव पड़ा है और इस बात की आवश्यकता है कि योजना की शेष अवधि में सरकार और जनता द्वारा और अधिक परिश्रम किया जाए। मेरी सरकार इस बात को भली प्रकार जानती है।

[राष्ट्रपति]

देश की आर्थिक स्थिति, विशेषकर योजना से सम्बन्ध रखने वाली बातें जो इस समय हमारे सामने हैं, गम्भीर चिन्तन का विषय हैं और मेरे मन्त्रियों का ध्यान उस ओर है, किन्तु इस स्थिति को भयावह कहना गलत होगा। केन्द्रीय और राज्यों के घाटे के बजट, योजना की आवश्यकताएँ, विदेशी विनिमय के साधनों का अभाव और कुछ बाहरी मामले इस बात की मांग करते हैं कि हम दृढ़ और योजनाबद्ध प्रयत्न करें। आवश्यकता इस बात की है कि हम साधनों को सुरक्षित रखें और मितव्ययता द्वारा कुछ चीजों के आयात पर प्रतिबन्ध, निर्यात व्यापार के विस्तार और उद्योग तथा कृषि के क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता में वृद्धि द्वारा इन माध्यमों का विस्तार करें। इस बात की भी जरूरत है कि उत्पादक कार्यों के लिए धन जुटाया जाय, अन्तः उत्पादक कामों को हाथ में न लिया जाए और अतिसंग्रह और सट्टे की समाज-विरोधी प्रवृत्तियों का दमन किया जाय। केवल सरकार द्वारा ही नहीं बल्कि जनता द्वारा भी प्रयत्न करने और सावधान रहने से ही इस काम में ठोस सफलता प्राप्त हो सकती है।

जिन कमियों का मैंने जिक्र किया है उन्हें दूर करने का अधिक आसान तरीका यह हो सकता है कि हम निर्माण-सम्बन्धी काम को स्थगित कर दें पर वह तरीका रचनात्मक या लाभदायक नहीं है, क्योंकि समस्या को मुलम्माने का यह सच्चा या स्थायी उपाय नहीं है। हमें अधिक उत्पादन करने और निर्माणकार्य में सुधार को बनाए रखने के लिए अपने साधनों को जुटाना है और उन्हें सुरक्षित रखना है। मेरी सरकार इस समस्या और इसके लिए आवश्यक प्रयत्न से पूर्ण रूप से अवगत है। उसे इस बात की भी चिन्ता है कि इन तात्कालिक कठिनाइयों के कारण उन्नति के मार्ग में बाधा न पड़न पावे और जहां जैसी जरूरत हो कार्यप्रणाली में संशोधन

द्वारा या योजनानुसार साधनों को जुटा कर उन कठिनाइयों पर काबू पाया जावे और किसी भी अवस्था में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और विकास की गति धीमी न होने दी जावे।

ऐसे प्रयत्न की सफलता में जनमत का बहुत बड़ा स्थान है, और यह प्रायः निर्णायक सिद्ध होता है। जनसाधारण का दृढ़ निश्चय और जोश, अनुशासन में रहने के लिए उनकी तत्परता, प्रयत्नों के लिए आवाहन का स्वागत और समाज-विरोधी व्यवहार, जैसे अतिसंचय, फिज़ूलखर्ची आदि की रोकथाम करने का उनका संकल्प ही देश के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के इस संकटकाल को पार करने में सहायक होगा।

संसद् के सदस्यगण, इस सम्बन्ध में मेरी सरकार जो नीति अनायेगी तथा प्रयास करेगी, जिनके द्वारा कठिनाइयाँ दूर कर हमें सफलता प्राप्त करनी है, उस नीति के समर्थन के लिए विशेष तथा सतत प्रयत्न की देश आप से बहुत आशा करता है।

यद्यपि अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है और दैवी विपत्तियों के कारण जो हानि हुई है, विशेषकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, उसे छोड़ कर वृद्धि बराबर बनी रही है, हमें खाद्य के सम्बन्ध में देश को आत्म-भरित बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। अनाज की चढ़ी हुई कीमतों के गिरने के कुछ लक्षण दिखाई दिये हैं और मेरी सरकार ने कीमतों को कम करने के लिए बहुत से उपाय किये हैं। भरपूर प्रयत्नों के फलस्वरूप अनाज का उत्पादन बढ़ा है और फसल में सुधार हुआ है। कुछ मोटे अनाजों को छोड़कर, जिन पर जलवायु का बुरा प्रभाव पड़ा है, अनुमान है कि दूसरे अनाजों का उत्पादन यही नहीं कि कम नहीं हुआ बल्कि पहले से बहुत बढ़ा भी है।

अभी जो अभाव है उसे दूर करने और कीमतों में तेजी लाने के लिए सुरक्षित अन्न

भण्डार तैयार करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने विदेशों से अनाज आयात करने की व्यवस्था की है। अनाज भण्डार बनाने का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। अनाज की कीमतों में तेजी रोकने के लिए, जो स्थिति अभाव की आशंका और घबराहट तथा अतिसंचय करने की प्रवृत्ति से पैदा होती है, जनता का हक निर्णायक होता है और उसका बहुत महत्व है। सरकार ने जो रुढ़म उठाये हैं उनके परिणाम स्वरूप और उत्पादन में वृद्धि के कारण खाद्य की स्थिति ऐसी नहीं है कि जनता किसी भी प्रकार के अविश्वास की भावना को स्थान दे। अनाज की उपलब्धि और आवश्यकता के बारे में मेरी सरकार का यह विचार है कि वह समय समय पर संसद को खाद्य-स्थिति से अवगत करावेगी। आशा है कि अनाज के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त होने से निराधार आशंका, कृत्रिम अभाव और कीमतों की तेजी—इन तीनों की रोक-थाम हो सकेगी।

मेरी सरकार को यह बताने में खुशी होती है कि सामुदायिक योजना सम्बन्धी कार्यक्रम में उन्होंने अनाज के उत्पादन पर जो जोर देने निश्चय किया था, उसके फलस्वरूप बहुत लाभ हुआ है। सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विकास सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। खेती, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्रों में हमारे जो लक्ष्य थे, सफलता उनसे भी अधिक रही है। राष्ट्रीय निदर्शन अवीक्षण (नैशनल साम्पल सर्वे) के अनुसार, पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तिम काल में, सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विकास सेवा मंडलों के क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन सारे देश के मुकाबले में प्रायः २५ प्रतिशत अधिक हुआ। सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विकास सेवा के अन्तर्गत इस समय २,२२,००० ग्राम हैं।

सरकारी व्यवसायों की उल्लेखनीय उन्नति रही है और प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन

निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा। व्यवसाय के निजी क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। एक परिनियत संस्था के रूप में, खादी और ग्रामोद्योग कमिशन की नियुक्ति से, ग्रामोद्योगों तथा खादी को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। नई बड़ी योजनाओं में, जिस योजना का हाल ही में उद्घाटन होने जा रहा है वह निविली लिग्नाइट योजना है, जिस पर कार्य इसी महीने आरम्भ हो रहा है। मेरी सरकार भारी मशीनों के निर्माण के लिए कारखानों की स्थापना को महत्वपूर्ण मानती है और इस दिशा में कार्यवाही कर रही है।

विदेशी विनिमय के साधनों पर दबाव कम करने के लिये, बड़ी योजनाओं के सम्बन्ध में मेरी सरकार ने बाद में दाम चुकाने की व्यवस्था की है। कुछ योजनाओं के सम्बन्ध में दीर्घकालीन उधार की व्यवस्था की जा रही है।

राज्यों के पुनर्गठन के बाद, संघीय प्रदेशों के लिए परामर्श-दात्री समितियाँ नियुक्त की गई हैं और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा के लिए प्रदेशीय परिषदों की स्थापना की गई है। दिल्ली के लिए शीघ्र ही एक निगम स्थापित होगा। लखदीव, मिनिकोय और अमनदीव द्वीपों को मिला कर एक नवीन संघीय प्रदेश बनाया गया है और अग्निमान द्वीपों के लिये पंचवर्षीय योजना में ५,६२,५०,००० रुपये के खर्च की व्यवस्था की गई है, जिससे और कामों के अतिरिक्त इस द्वीप समूह और भारत के बीच यातायात की उचित व्यवस्था भी की जायगी।

जहाज-घाटों और आधुनिक ढंग के जहाजों के निर्माण के काम में भी विशाल-पट्टम में बहुत प्रगति हुई है और एक दूसरे जहाज-घाट के निर्माण की योजना इस समय हाथ में है।

मेरी सरकार ने हाल ही में घरों की कमी दूर करने और निवास-सम्बन्धी स्तर को ऊंचा करने, गन्दी बस्तियों में सुधार करने, बगीचों में घरों की व्यवस्था करने और औद्योगिक

[राष्ट्रपति]

क्षेत्रों में तथा कम आमदनी वाले लोगों के लिए घरों की व्यवस्था करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। दिल्ली और भारत के दूसरे बड़े शहरों में गन्दी बस्तियों में सुधार करने की तात्कालिक आवश्यकता है और इस समस्या पर कन्द्रीय सरकार, राज्यों की सरकारें और सम्बन्धित निगम पूरा ध्यान दे रहे हैं।

संसद् के पिछले सत्र के बाद दो अध्यादेश जारी किए गए हैं। तत्सम्बन्धी विधेयक संसद् के सामने रखे जायेंगे। वे इस प्रकार हैं।

(१) जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश, १९५७।

(२) औद्योगिक झगड़े (संशोधन) अध्यादेश, १९५७।

चालू सत्र में मेरी सरकार संसद् के समक्ष कई और विधेयक प्रस्तुत करेगी।

१९५७-५८ का आय-व्यय सम्बन्धी अन्तरिम विवरण संसद् के पिछले सत्र में पेश किया गया था और मतदान द्वारा वर्ष के एक भाग के लिए खर्च की मंजूरी ली गई थी। आय-व्यय का वह विवरण आवश्यक संशोधनों के साथ संसद् के इस सत्र में फिर पेश किया जाएगा, और वर्ष भर के खर्च के लिए संसद् का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

विदेशों से हमारे सम्बन्ध मंत्रीपूर्ण चले आ रहे हैं। संसद् के समक्ष पछली बार मैंने जब भाषण दिया था उसके बाद हमें पोलैंड के प्रधान मंत्री, श्री जोज्फ सिरेकीविज, संघीय जर्मन गणतन्त्र के विदेश मन्त्री, डा० हेनरीश वान ब्रेन्टानो और चिली के विदेश मन्त्री, श्री कोस्काल्डो सेन्ट मेरी का भारतीय गणराज्य के अभ्यागतों के रूप में स्वागत करने का सौभाग्य हुआ है।

जून के अन्त में लन्दन में होने वाले राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में मेरे प्रधान मंत्री भाग लेंगे। इस विदेश प्रवास

के समय वे सीरिया, डेन्मार्क, फ़िनलैंड, नावें, स्वीडन, नैदरलैंड, मिस्र और सूडान की भी यात्रा करेंगे।

मध्यपूर्व में स्थिति संतोषजनक नहीं और वहां तनाव बराबर बना है, फिर भी यह हर्ष का विषय है कि स्वेज नहर जहाजरानी के लिए फिर से खुल गई है। नहर खोलने से पहले मिस्र की सरकार ने एक घोषणा की थी जो १८८८ की संप्रतिज्ञा को पुष्ट करती है और अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र के सिद्धान्तों का मिस्र द्वारा अनुसरण करने का दृढ़ निश्चय प्रकट करती है। बारे सपकार उस घोषणा का स्वागत करती है। उस घोषणा में यह व्यवस्था की गई है कि संप्रतिज्ञा की व्याख्या अथवा उसके लागू किए जाने के सम्बन्ध में और कुछ जरूरी मामलों के बारे में जो विवाद पैदा हों उन्हें निर्णय के लिए विश्व न्यायालय के सामने पेश किया जाए और इस न्यायालय के फैसले को बाध्य समझ जाय। मेरी सरकार की राय में उस घोषणा की प्रभुत धारार्थे युक्तिसंगत हैं और यदि सभी संलक्षित पक्ष पारस्परिक सद्भावना तथा सहयोग की भावना से उन पर अमल करें, वे संसार के राष्ट्रों के उचित हितों की रक्षा करने के लिये काफी हैं। इस घोषणा का एक महत्वपूर्ण पहलु यह है कि यद्यपि यह मिस्र की सरकार द्वारा की गई है, उसने यह घोषित किया है कि इस घोषणा का दर्जा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का होगा और यह घोषणा संयुक्त के दफ्तर में दर्ज कर दी गयी है। मेरी सरकार का विचार है कि इस घोषणा और इस के अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दर्जे ने उस क्षेत्र में तनाव की भावना को कम करने के मागे को प्रशस्त किया है और उसके द्वारा उन सभी समस्याओं को सुलझाने का जो स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद पैदा हुई थीं, रास्ता निकल सकेगा।

सुरक्षा-परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष, डा० गुनार यारिंग ने, २१ फरवरी को कश्मीर

सम्बन्धी विवाद के अन्त में सुरक्षा-परिषद् द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव के अनुसार, पाकिस्तान और भारत की यात्रा की। डा० यारिंग दो बार भारत आये और उन्होंने मेरे प्रधान मंत्री से बातचीत की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सुरक्षा-परिषद् को दे दी है।

निःशस्त्रीकरण कमिशन की उप-समिति की बैठक कुछ समय से लन्दन में हो रही है, किन्तु, निःशस्त्रीकरण के किसी भी पहलू पर अभी कोई समझौता हुआ नहीं जान पड़ता है। आणविक तथा परमाणविक शस्त्रों के विस्फोट रोकने के सम्बन्ध में भी कोई समझौता नहीं हुआ है। निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में मेरी सरकार के प्रस्ताव एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के द्वारा अन्य प्रस्तावों के साथ निःशस्त्रीकरण कमिशन के पास भेज दिये गये।

इस बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ और अब ब्रिटेन भी सार्वजनिक विध्वंस के इन शस्त्रों के विस्फोट-सम्बन्धी प्रयोग करते रहे हैं। इन विस्फोटों का विपरीत प्रभाव संसार के विभिन्न भागों में अधिकाधिक देखा जाने लगा है और विश्व जनमत इन विस्फोटों द्वारा होने वाली हिंसा से चिन्तित हो उठा है। इन विस्फोटों को बन्द करने की मांग व्यापक है और आणविक शक्तियों को इस से बराबर अवगत किया जा रहा है, किन्तु, अभी तक इसका कुछ परिणाम नहीं निकला।

मेरी सरकार का मत है कि विभिन्न देशों द्वारा इन विस्फोटों को सीमाबद्ध और पूर्वसूचित करने के सम्बन्ध में जो सुझाव किये गये हैं, उन से यह आशा नहीं होती कि विस्फोटों के हानिकार प्रभावों से वे संसार को सुरक्षित रख सकेंगे अथवा इन विध्वंस शस्त्रों के बहिष्कार का मार्ग खोज सकेंगे। इसके विपरीत, इन प्रयोगों के किसी भी प्रकार के नियमन का एकमात्र परिणाम यह होगा कि लोग आणविक तथा परमाणविक युद्ध को न्यायोचित और विश्व जनमत द्वारा समर्थित

समझने लगेंगे। युद्ध के अधिक से अधिक घातक शस्त्रों के प्रयोग की खबरें बराबर आ रही हैं। संतोष की बात केवल यही है कि संसार का जनमत इन प्रयोगों का आज पूर्वापेक्षित अधिक विरोधी है। अप्रैल, १९५४, में मेरे प्रधान मंत्री ने, लोक-सभा के सामने एक वक्तव्य में इन विस्फोटों की रोक के सम्बन्ध में "यथा स्थिति" समझौते के रूप में कुछ प्रस्ताव रखे थे। तब से इन प्रस्तावों को विभिन्न देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है और काफी जनमत इनके पक्ष में है। विश्व के दूसरे राष्ट्रों के साथ, मेरी सरकार इन प्रयोगों की रोक-थाम और आणविक तथा परमाणविक शस्त्रों के बहिष्कार के लिए दूसरे राष्ट्रों और विश्व-परिषदों के समक्ष बराबर अपना प्रभाव डालती रहेगी।

आज हम उस महान विद्रोह के पूरे एक सौ वर्ष बाद मिल रहे हैं जो मेरठ में आरम्भ हुआ था और बाद में भारत के अधिकांश भागों में फैल गया था। इस देश में विदेशी शासन को वह पहली प्रमुख चुनौती थी और इसके कारण कुछ विभूतियां प्रकाश में आयीं जो हमारे देश के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इस विद्रोह का नृशंसता के साथ दमन किया गया, किन्तु स्वाधीनता की भावना और विदेशी शासन से मुक्त होने की इच्छा दबाई नहीं जा सकी और बाद में अनेक अवसरों पर वह ज्वल रही। अन्त में, उस ने एक महान राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप लिया, जो अहिंसा और शांति के सिद्धान्तों पर चला और जिसके फल-स्वरूप हम स्वाधीनता प्राप्त करने और भारतीय गण-राज्य की स्थापना करने में सफल हुए। उन सब के प्रति, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जीवन की आहुति दी अथवा नाना प्रकार के कष्ट सह्य, हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

भारत को स्वाधीन हुए आज करीब १० वर्ष हो चुके हैं और इस अवधि में संसद् देश की जनता की उन्नति तथा कल्याण और विश्व में सहयोग तथा शांति स्थापन के लिए प्रयत्न-

[राष्ट्रपति]

शील रही है। इन प्रयत्नों का फल काफी ठोस रहा है जो हमें इस देश में चारों ओर दिखाई देता है। इन वर्षों में जो चहुंमुखी उन्नति हम ने की है उससे लोगों में आशा और आत्म-विश्वास की भावना पैदा हुई है। भावी निर्माण और विकास की यह सुदृढ़ नींव है।

देश के बाहर मेरी सरकार का जोरदार प्रयत्न रहा है कि संसार में तनाव की भावना को कम किया जाय और विश्व-शांति के पक्ष को दृढ़ बनाया जाय। इस विचारधारा के परिणाम-स्वरूप, अपनी नीति को स्वाधीन रखने के लिये और कोरिया, इण्डो-चाइना और अब मध्यपूर्व में भी शांति की स्थापना में योगदान देने के लिये, हमारे देश ने भारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली हैं।

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में हमारे सामने जो काम हैं वे बहुत अधिक ही नहीं कभी कभी बहुत भारी भी दिखाई देते हैं। किन्तु, यदि स्वाधीनता को देश के लोगों के लिये बरदान बनाना है और यदि सतत तनाव और भावी विभीषिका से संसार को मुक्त कराने में हमें सहायक होना है, तो ये सब काम हमें करने होंगे, कठिनाइयों पर विजय पानी होगी और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किये हैं उन्हें प्राप्त करना होगा।

इन सभी दिशाओं में मेरी सरकार बराबर यथा-शक्ति प्रयत्न करती रहेगी। यह धारणा कि उसे देश की जनता का समर्थन प्राप्त है और यह अडिग विश्वास कि युद्ध के उमड़ते हुए बादलों और निराशा के बावजूद भी मानव जाति में प्रगति करने और जीवित रहने की नैसर्गिक आकांक्षा है, मेरी सरकार का बल है। हमारी क्षमता और साधन सीमित हैं और संसार में हमारी आवाज संभवतः बहुत ऊंची नहीं है, किन्तु, राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से, हमारे इतिहास और परम्पराओं तथा विश्वासों को देखते हुए हम किसी और गृस्ते को नहीं अपना सकते। यह सीमाव्यय का विषय है कि

संसार भर के सभी लोगों का यह सामान्य ध्येय और उत्कृष्ट इच्छा है।

संसद् के सदस्यगण, मैं आपके प्रयत्नों में आप सब की सफलता की कामना करता हूँ।

The President: Members of Parliament, you and the members of the legislatures of the States, chosen by an electorate of nearly two hundred million voters of our country, in accord with our Constitutional procedures, have called me once again to the high office of the President of the Republic. I am deeply conscious of the honour and I am grateful for the confidence which you have reposed in me. It shall be my endeavour to continue to deserve the trust and the affection of which I have been so long the happy recipient.

It gives me great pleasure to welcome you, as Members of the Second Parliament in the history of our Republic. Some of you have been members of one or other of the Houses of Parliament, or come to Parliament with rich experience in your State legislatures. There are others among you who have been elected to Parliament for the first time. All of you will find, in your life and duties as Members of Parliament, both in the legislature and your constituencies, immense and varied opportunities and fields of constructive work in the service of our country and people. I wish you all good fortune and a very successful tenure of Parliamentary life.

We are in the second year of our Second Five Year Plan. There has been some inevitable slowing down in the first year of the Plan, resulting partly from the reorganisation of the States. This imposes a greater strain and calls for added effort both by the Government and the people during the remaining period of that Plan. My Government are fully conscious of this.

The economic situation, more particularly in relation to the Plan, confronts us with factors which, while

they do not warrant grave apprehensions, are matters of serious concern and they are engaging the attention of my Ministers. The deficit in the Central and State budgets and the strain on our foreign exchange resources occasioned by the requirements of the Plan and of industrial development generally, as well as by external factors, call for determined and planned efforts. They call for both conservation and expansion of our resources by effecting real economies, by planned restrictions of certain imports, by expansion of export trade and by increasing national self-sufficiency both in the fields of industry and agriculture. They will call for savings to be utilised for production and the abandonment of unproductive and anti-social habits of hoarding and speculation. These can only be effectively achieved by efforts and vigilance not only on the part of Government but by the people as well.

It would be the easier, but not the gainful or constructive way, to bridge the gaps to which I have referred, by halting development. This will, however, provide no real or long term remedy. Our endeavour has to be to mobilise and conserve resources for greater productivity and for maintaining and improving development. My Government are fully aware of the problem and of the effort required. They are equally concerned that our temporary difficulties should not lead us in the direction of retarding progress and development, but that the difficulties should be overcome, where necessary, by reconsideration and revision of methods and by planned mobilisation of resources, and not by either the abandoned or slowing down of the progress towards our objectives.

Public opinion plays a large and well-nigh conclusive part in the success of such endeavour. The determination and fervour of our people, their readiness to accept discipline to respond to the call for efforts and

their resolve not to be led into anti-social behaviour, such as by hoarding or wasteful spending, alone will help the country to pass successfully through the present crucial period of our Second Five Year Plan.

Members of Parliament! the country looks to you a great deal for that sustained and special effort in support of the policies and endeavours which my Government will initiate in this behalf, which will help us to surmount difficulties and to achieve success.

While food production has increased and the increases have been maintained, except for the results of natural calamities, more especially in certain parts of Bihar and the eastern districts of Uttar Pradesh, we have a considerable way to go before our country becomes fully self-sufficient in food. There are signs of slight abatement in the rising trend of food prices and my Government have taken several measures to bring about this trend. Intensive efforts have increased food production and improved crop prospects. Except in the case of some of the coarse grains adversely affected by climatic conditions, the crop yields and estimates not only do not indicate a shortfall but have recorded appreciable increases.

My Government have also entered into arrangements for necessary imports of food grains and for building up reserves which will prevent price increases and bridge the gaps that still remain. A large storage construction programme has been undertaken. The behaviour of the public is a large and often determining factor in preventing rise in food prices which is often caused by the apprehension of shortages resulting in the resort to hoarding as well as to the tendency to panic. The food situation, thanks to the increased production and the steps taken by my Government, does not warrant any lack of public confidence in regard to supplies. My Government propose to keep Parliament informed of the position in regard to food and the estimates of supply and requirements. It may be

[The President]

hoped that a knowledge of the true facts will help to allay needless apprehensions and prevent artificial shortages and higher prices.

My Government are happy to state that their decision to lay stress on food production and agriculture generally in the Community Project plans has yielded handsome results. The Community Development and the National Extension Service programmes have made great strides in achievement. Higher targets in agriculture, health and sanitation have been achieved. The National Sample Survey shows that, at the end of the first Five Year Plan, the crop yields in the Community Development Project and National Extension Service Blocks areas were approximately 25 per cent. higher than for the country as a whole. The Community Projects and National Extension Blocks now cover 222 thousand villages.

State undertakings continue to make notable progress and new targets have been reached in almost every enterprise. There has also been expansion in the private sector. Khadi and Village industries will receive a further impetus with the setting up of "The Khadi and Village Industries Commission" as a statutory body. Among the major new projects that will soon be inaugurated is the Nayveli Lignite Project where the first mine-cut will be made this month. My Government attach importance to the building up of a plant for the manufacture of heavy machinery and steps are being taken to this end.

To reduce the pressure on our resources of foreign exchange, my Government are making efforts to obtain deferred payment arrangements for major projects. Long term credits for certain projects are being negotiated.

Consequent on the reorganisation of the States, Advisory Committees have been set up for the Union Territories and Territorial Councils have been established in Himachal Pradesh, Manipur and Tripura. A Corporation

for Delhi will be soon established. A new Union Territory of the Laccadives, Minicoy and Amindivi Islands has come into existence and the Five Year Plan for the Andaman Islands at a total cost of 592.50 lakhs will include the development of communication between the islands and the mainland.

Shipyard construction and the building of ships of modern design have made great progress at Visakhapatnam and plans for a second shipyard are now in hand.

My Government have initiated measures to relieve housing shortages and promote housing standards, slum clearances and Plantation Housing Schemes and housing for low-income groups and subsidised industrial housing. An urgent requirement of Delhi and the other great cities of India is the clearance of slum areas, and this problem is receiving the consideration of the Central and State Governments and the Corporations concerned.

Two Ordinances have been promulgated since the last session of Parliament. Bills dealing with these Ordinances will be placed before Parliament. These are:—

(i) The Life Insurance Corporation (Amendment) Ordinance, 1957.

(ii) The Industrial Disputes (Amendment) Ordinance, 1957.

My Government will also submit to Parliament a number of other Bills during the current session.

An interim statement of revenue and expenditure for 1957-58 was presented to Parliament during its last session and votes on account authorising expenditure for a part of the year were passed. That statement of revenue and expenditure will be presented again to Parliament in this session with such changes as are considered necessary, and Parliament will be asked to approve funds for the whole year.

Our relations with foreign countries continue to be friendly. Since I addressed Parliament last, we have had the pleasure of receiving as the guests of the Republic, Mr. Jozef Cyrankiewicz, Prime Minister of Poland, Dr. Heinrich Von Brentano, Foreign Minister of the Federal German Republic, and Mr. Osvaldo Saint Marie, Foreign Minister of Chile.

My Prime Minister will attend the meeting of Commonwealth Prime Ministers in London at the end of June. During his absence abroad, he will take the opportunity of visiting Syria, Denmark, Finland, Norway, Sweden, the Netherlands, Egypt and Sudan.

While the situation in the Middle East continues to be unsatisfactory and charged with tension, it is a matter of gratification that the Suez Canal has been re-opened for navigation. My Government welcome the Declaration made by the Government of Egypt, prior to the opening of the Canal, which re-affirms the Convention of 1888 and the determination of Egypt to continue to abide by the principles of the Charter of the United Nations and of International Law. The Declaration provides for the reference of disputes arising from interpretation of the Convention and its application as well as certain other matters to the World Court and also to abide by its decisions. The main provisions in the Declaration are, in the view of my Government, reasonable and adequate to safeguard the legitimate interests of the world community, if they are worked in a spirit of cooperation and mutual understanding by all concerned. A notable feature of the Declaration is that, while it is made by the Government of Egypt, that Government has declared that it has the status of an International Instrument and this has been registered with the United Nations. My Government feel that this Declaration and its status as an International Instrument is a notable contribution to the lowering of tensions in that area and will provide a

solution of the difficulties that followed the nationalisation of the Suez Canal.

Dr. Gunnar Jarring, a former President of the Security Council, visited Pakistan and India in pursuance of a Resolution passed by the Security Council on the 21st of February this year at the end of the debate on Kashmir. Dr. Jarring visited India twice and conferred with my Prime Minister. He has submitted a report to the Security Council.

The sub-committee of the Disarmament Commission has been sitting in London for some time, but no agreement appears to have been reached on any aspect of Disarmament, including the suspension of explosions of nuclear and thermo-nuclear weapons. The proposals of my Government in regard to Disarmament were once again referred by the General Assembly of the United Nations at the last session, along with all other proposals, to the Disarmament Commission.

Meanwhile, the United States, the Soviet Union, and now the United Kingdom continue their experiments to explode these weapons of mass destruction. World opinion is increasingly concerned about the harmful effects of radiation which has been increasingly and more frequently felt in various parts of the world. The demand for the suspension of these explosions is widespread and continues to be impressed upon the nuclear powers, but hitherto without success.

My Government do not consider that the compromise proposals suggested from diverse quarters for the so-called limitation of these explosions or for their registration will ever rid the world of their harmful effects, or open the way to the abandonment of these weapons of mass destruction. On the other hand, such regularisation of these tests tends to make thermo-nuclear war legitimate and as having the sanction of the world community. Reports of experiments with more

[The President]

and more deadly weapons of war continue to be received. It is however a matter of some gratification that the volume of world opinion against the continuance of experiments has reached a higher level than ever before. My Prime Minister in a statement before the Lok Sabha in April 1954 put forward for consideration the proposal for a "Standstill Agreement" to suspend these explosions. These proposals have since gained much support and the movement of world opinion in favour of it has gathered momentum. My Government will continue to exert their influence with other nations and in the counsels of the world to bring about the abandonment of these test explosions and the prohibition of nuclear and thermo-nuclear weapons.

We meet here today one hundred years after the great rising which began in Meerut and spread over considerable parts of India. That was the first major challenge to foreign rule and it threw up notable figures, famous in India's history. The uprising was cruelly suppressed, but the spirit of freedom and the desire to be free from foreign domination continued and found expression on many subsequent occasions. Ultimately it led to a great national movement which followed peaceful methods and succeeded in achieving the independence of India and the establishment of this Republic of ours. We pay tribute now to all those who gave their lives or otherwise suffered so that India may be free.

India has been independent for nearly ten years now and during this period Parliament has laboured for the well-being and advancement of this country and her people and for peace and cooperation in the world. These labours have produced substantial results which we see all round us in the country. The progress we have made during these years in our own land has produced in our people hope and self-reliance. This

is a substantial foundation on which we can build for the future.

Abroad, my Government have striven strenuously to help to lower existing tensions in the world and to serve the cause of peace. The country has also accepted heavy responsibilities in the pursuit of this policy, in regard to maintaining the independence of its approach as well as in making contributions to the maintenance of peace, as in Korea, Indo-China and now in the Middle East.

The tasks that confront us both at home and abroad are not only considerable but at times appear overwhelming. But these tasks have to be faced, difficulties surmounted and objectives achieved if the fruits of independence are to be ensured to our people and if we are to help the world being spared the continual stress and horror of impending catastrophe.

My Government will continue their strenuous endeavours in all these directions, to the best of their capacity conscious of the confidence reposed in them by the country, and fortified by the conviction that despite clouds of war, and even despair, the desire for survival and progress is inherent in humanity. Our capacities and resources are limited and our voice in the world may be but small. But neither our national interests nor our history and traditions, nor our convictions chart any other course for us. Happily for us, this is the common aim and the firm desire of all our people.

Members of Parliament, I wish you success in your labours.

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

Secretary: Sir, I lay on the Table the following 9 Bills passed by the Houses of Parliament during the Fifteenth Session of First Lok Sabha and assented to by the President